समावेश

एक पहल...

अंक 1, अगस्त–अक्टूबर 2010

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित

संपादक की कलम से...

समावेश का प्रथम अंक प्रकाशित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। हमारे देश में लगभग 2.19 करोड़ विकलांगजन हैं। विकलांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सभी का नैतिक दायित्व है। मुझे खुशी है कि विकलांगजनों के प्रति जनसमुदाय में सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। विकलांगजन बेहतर जीवन जी सकते हैं यदि उनके पास समान अवसर एवं पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए प्रभावी पहुंच हो।

समावेश के इस अंक में कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा साइट सेवर्स के सहयोग से चलाये जा रहे "समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम" को प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही विकलांग जनों से संबन्धित जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आशा है कि प्रथम अंक में दी जा रही जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस अंक के बारे में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

आशीष त्रिपाठी
समन्वयक
कट्स मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम
(Community Based Rehabilitation Programme)

हमारे देश में विकलांगजन विभिन्न प्रकार के सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित हैं एवं दोहरी उपेक्षा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी आवश्यकताऐं एवं अधिकार लगातार नजर अंदाज किये जा रहे हैं। विकलांगजनों को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शामिल करना प्रत्येक विकासात्मक पहल का अंग होना चाहिए जिससे उन्हें समान अवसर तथा अधिकार सुनिश्चित हों और पीढ़ियों से व्याप्त सामाजिक बाधाऐं दूर हो सकें। आज जरूरत ऐसे मंच की है जहाँ पर विकलांग अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सहज रूप से सम्पर्क कर सकें एवं उन्हे त्वरित सहयोग मिले। ऐसे वातावरण हेतु सरकारी, गैर सरकारी, कोरपोरेट सेक्टर, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों की अहम भूमिका बन जाती है।

अगस्त 1, 2010 से साईटसेवर्स के सहयोग से कट्स मानव विकास केन्द्र द्वारा 'समुदाय आधारित पुनर्वास' कार्यक्रम का संचालन चित्तौड़गढ़ जिले की चित्तौड़गढ़ एवं निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के 406 गाँवों में किया जा रहा है।

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम का लक्ष्य है – 'चित्तौड़गढ़ जिले में बिना कारण के कोई भी व्यक्ति अंधा ना रहे एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी अन्धता ठीक नही हो सकती और अल्प दृष्टि व्यक्तियों को भी वही अधिकार प्राप्त हों जो कि आम नागरिक को प्राप्त हैं।' परियोजना का उद्देश्य लक्षित क्षेत्र में नेत्र स्वास्थ्य के प्रति समुदाय का ज्ञान बढ़ाना है ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पाएं एवं दृष्टि बाधित लोग अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाकर नियमित सेवाओं और अवसरों का लाभ उठा पायें एवं समुदाय में सक्रिय योगदान दे सकें।

कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम

- आँखों की प्राथमिक देखभाल, बचाव, इलाज और अन्धता के कारणों एवं सामाजिक समावेश पर काम करने का तरीका प्रदर्शित करना।
- सरकारी एवं गैर सरकारी सहभागिता से चिन्हित व्यक्ति, जिनकी आँखों में इलाज योग्य समस्याऐं हैं उन्हे समुचित इलाज सुनिश्चित करवाने का तरीका प्रदर्शित करना।
- विकलांगजनों का क्षमतावर्धन करना और उन्हें एक जिला स्तरीय नेटवर्क के रूप में संगठित करना। सभी चिन्हित दृष्टि बाधित बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में नामांकन करवाकर गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कर सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करना।
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सामाजिक समावेश को बढ़ाने की दिशा में काम करना और सुनिश्चित करना कि चिन्हित दृष्टिबाधित व्यक्तियों में से कम से कम 70 प्रतिशत को समय से जरूरत आधारित पुनर्वास सुविधाऐं प्राप्त हो सकें।
- कट्स के कार्यक्रम एवं संस्था के स्तर पर विकलांगता को मुख्यधारा में शामिल करना एवं संस्था की क्षमताओं को बढ़ाना जिससे कि कट्स दक्षिणी राजस्थान में संदर्भ संस्थान के रूप में कार्य कर सके।

विकलांगजनों की स्थिति

विकलांगजनों को मिले प्राथमिकता

कार्यशाला को सम्बोधित करते साईटसेवर्स के केतन कोठारी

कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ द्वारा साइट सेवर्स के सहयोग से संचालित ''समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 3 सितम्बर 2010 को पंचायत समिति सभागार चित्तौड़गढ़ में ''विकास योजनाऐं एवं विकलांगता'' विषय पर एक जिला स्तरीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में उपखण्ड अधिकारी श्री अमरसिंह कानावत ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से विकलांगों को प्राथमिकता से लाभान्वित करना सरकार का कर्तव्य एवं समाज का दायित्व है। विकलांगता के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास में सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि विकलांगता को आत्मसात कर ही विकलांगता के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है। श्री कानावत ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में चित्तौड़गढ़ जिले में विकलांगजनों को राजस्थान में सबसे अधिक लाभान्वित कर एक मिसाल कायम की है।

साइट सेवर्स के कार्यक्रम प्रभारी श्री प्रभात सिन्हा ने बताया कि गरीबी व विकलांगता एक दूसरे के पूरक हैं। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को विकलांगता के साथ जोड़ते हुए कहा कि गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, में विकलांगजनों का उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मुंबई से आये साइटसेवर्स के श्री केतन कोठारी जो स्वयं बचपन से नेत्रहीन हैं और आज अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम हैं, उन्होंने विकलांगजन के प्रति समानुभुति की भावना विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विकलांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप योजना बने एवं योजनाऐं धरातल स्तर तक पहुंचनी चाहिए और उनसे जुड़ी योजना बनाने में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ के केन्द्र समन्वयक श्री आशीष त्रिपाठी ने चित्तौड़गढ़ जिले में नेत्र स्वास्थ्य की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले का स्थान नीचे से दूसरा है क्योंकि राजस्थान का कैटरैक्ट (मोतियाबिन्द) सर्जिकल अनुपात प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 3961 है, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में मात्र 1396 है। पिछले वर्ष सरकारी अस्पताल में आंखों के मात्र 94 ऑपरेशन हुए हैं। उन्होनें विकलांगता के बारे में आंकडों की सही पहचान होने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धक श्री पंकज यादव ने कहा कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में विकलांगजनों की भागीदारी बढ़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री शरद शर्मा ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में विकलांग लोगों का सर्वे किया जाएगा।

बैंक आफ बड़ोदा के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री हरिश पालीवाल ने अधिक से अधिक विकलांगजनों को बैंक से जोड़ने का आश्वासन दिया। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के विकास अधिकारी श्री के. एल. जैन ने सरकारी योजनाओ में विकलांगजनों को प्राथमिकता देने की बात कही।

जिला स्वयं सेवी संस्था मंच के अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी ने सरकार द्वारा करवाये जाने वाले सर्वे कार्य में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। गायत्री अस्पताल के संचालक हरि प्रसाद आमेट ने अस्थि विकलांगजनों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन किये जाने की जानकारी दी एवं भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग करने का आश्वासन दिया।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996 के नियमों में संशोधन

सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996 के नियमों में संशोधन किया गया है। पूर्व में राज्य में निःशक्त व्यक्तियों के लिये प्रमाण पत्र राजकीय अस्पतालों में व मेडिकल बोर्ड के द्वारा तीन विषय विशेषज्ञ के द्वारा बनाये जाने का निर्देश था जिसमें से एक विषय का विशेषज्ञ चिकित्सक होना आवश्यक है

परन्तु अब सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये गए हैं कि 'अब एक चिकित्सक जो विषय विशेषज्ञ हो के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। एक से ज्यादा विकलांगता होने पर सर्टिफिक्ट बोर्ड के द्वारा ही देय होगा।

चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच का पुनर्गठन

विकलांगजन किसी भी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित न हों एवं दोहरी उपेक्षा का अनुभव न करें। उनकी आवश्यकताऐं एवं अधिकार सुनिश्चित हों एवं हर विकास योजना में विकलांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये यह विचार 2 सितम्बर 2010 को आयोजित चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच की दिशा निर्धारण बैठक में उभरकर आये।

इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यक्रम क्षेत्र के विकलांगजनों को चिन्हित कर उन्हें एक मंच पर लाकर विकलांग मंच की दशा और दिशा पर मंथन कर उसे मजबूती प्रदान करना था ताकि वे अपने अधिकारों के लिये सजग होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

बैठक में कट्स के केन्द्र समन्वयक आशीष त्रिपाठी ने साईटसेवर्स के सहयोग से चलाई जा रही समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि सभी व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से विकलांग हैं उन सभी को समाज में आम नागरिक की तरह अपने अधिकार मिले। साथ ही विकलांगजनों को इतना सशक्त किया जाये कि वे अपने अधिकारों के लिये लड़ सकें।

साइटसेवर्स जयपुर के कार्यक्रम प्रबंधक प्रभात सिन्हा ने कहा कि विकास योजनाओं में विकलांगजनों की भागीदारी नगण्य है जोकि चिन्तनीय विषय है। चित्तौड़गढ़ जिले में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए एक भी अध्यापक नहीं होने पर उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने विकलांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

साइटसेवर्स मुंबई से आये कार्यक्रम अधिकारी केतन कोठारी जो जन्म से ही नेत्रहीन हैं लेकिन आज अपनी काबलियत और हिम्मत के चलते एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, ने बताया कि विकलांगता एक अवस्था है, बीमारी नहीं। विकलांगता को एक पीड़ा समाज ने बनाया है। हमारे देश में विकलांगजन एकजुट होकर अगर अपनी माँगें रखें तो उनकी आवाज को आगे तक पहुंचाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाये कि विकलांगता के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। संगठन की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि विकलांगजन अपने में आत्मविश्वास की भावना जागृत कर एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार द्वारा विकलांगजनों के लिए 19000 करोड़ रूपये की योजनाऐं बनी हैं जो धरातल स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं। श्री कोठारी ने कर्नाटक सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही मासिक पेंशन कम से कम 1000 रूपये होनी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच की दिशा निर्धारण बैठक

बैठक में जानकारी प्रदान करते चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच के प्रतिनिधि

अन्त में एक खुले मंच का आयोजन किया गया जिसमें सभी सहभागियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये। अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के जिला प्रभारी गंगाधर सोलंकी ने अपने विचार रखते हुये बताया कि आये दिन सड़कों पर वाहनों को तेज गति से दौड़ाने व ओवरलोडिंग के कारण हजारों लोग प्रतिदिन विकलांगता की श्रेणी में जुड़ रहे हैं। इस तरह की विकलांगता से लोगों को बचाने के लिये सरकार को यातायात अनियमितता के खिलाफ कोई न कोई कदम अवश्य ही उठाने चाहिये जिससे की इस तरह की विकलांगता से बचा जा सके।

जिला स्तरीय बैठक में 82 विकलांगजन सहित 150 लोगों ने भाग लिया।

प्रमुख घटकों के विचार

"विकलांगजन समाज का अभिन्न अंग हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके लिये पुनर्वास योजना की जरूरत है।"

— **श्री अमरसिंह कानावत**, उपखण्ड अधिकारी

"विकलांगजनों को सरकार की विकास योजनाओं से लाभान्वित करना पहली प्राथमिकता है।"

—**श्री के.एल.जैन,** विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़

"विकलांगजनों को आय संवर्धन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक दर्जा देना चाहिये।"

—**श्री पंकज यादव,** सहायक, महाप्रबंधक, नाबार्ड

"विकलांगजनों की स्थिति मजबूत करनी हो तो शिक्षा ही एक मात्र माध्यम है।"

—**श्री प्रभात सिन्हा,** कार्यक्रम प्रबंधक, साइटसेवर्स, जयपुर

"विकलांगों की पीड़ा विकलांग ही अच्छी तरह समझ सकता है, विकलांगों को एकजुट होने की आवश्यकता है।"

—**श्री उदयलाल गायरी,** प्रतिनिधि, विकलांग मंच

समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में स्टाफ आमुखीकरण

आमुखीकरण कार्यशाला में उपस्थित सहभागीगण

जोधपुर फलौदी में नेत्रहीन लोगों से सम्पर्क करते स्टाफ

सम्बोधित करते हुये साइटसेवर्स कार्यक्रम प्रभारी प्रभात सिन्हा

चित्तौड़गढ़ विकलांग मंच दिशा निर्धारण बैठक

सुदूर क्षेत्रों से पधारे सहभागी

कार्यशाला में जानकारी प्रदान करते हुये अतिथि

जिला स्तरीय हितधारक कार्यशाला में सम्बोधन करते एस.डी.एम

जिला स्तरीय कार्यशाला में भाग लेते हुये सहभागीगण

मीडिया

विकलांगों को लाभान्वित करना ही मकसद

'विकास योजनाएं एवं विकलांगता' विषय पर बैठक आयोजित

न्यूज सर्विस

चित्तौड़गढ़, 4 सितम्बर। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से विकलांगों को प्राथमिकता से लाभान्वित करना सरकार का कर्तव्य एवं समाज का दायित्व है। यह विचार कट्स द्वारा पंचायत समिति सभागार में 'विकास योजनाएं एवं विकलांगता' विषय पर

'विकलांगों की सेवा समाज का दायित्व'

पत्रिका संवाददाता @ चित्तौड़गढ़

सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से विकलांगों को करना समाज का दायित्व कट्स की ओर से पंचायत चित्तौड़गढ़ के सभागार में योजनाएं एवं विकलांगता आयोजित जिला स्तरीय बैठक में उपखण्ड अमरसिंह कानावत ने कही। कहा कि नरेगा योजना में जिले कलांगजनों को सबसे अधिक

विकलांगजनों की विकास योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाएं

न्यूज सर्विस

चित्तौड़गढ़, 2 सितम्बर। विकलांगजन किसी भी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार

'विकलांगों के अधिकार सुनिश्चित हों'

पत्रिका संवाददाता @ चित्तौड़गढ़

विकलांगजन किसी भी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित न हो एवं दोहरी उपेक्षा का शिकार नहीं कर हमारी आवश्यकताएं अधिकार सुनिश्चित किया जाए। विकास योजना में विकलांगजन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह विचार गुरुवार को सेंती में चित्तौड़गढ़

जिला विकलांग की दिशा निर्धारण बैठ में उभरकर सामने आए।

कट्स के केन्द्र समन्वयक आशीष त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में साइट सेवर्स प्रभात सिन्हा ने विकलांगजन के विकास की योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें मुम्बई के केतन कोठारी, कार्यक्रम प्रभारी मदनगिरी, उदयलाल गायरी, गायत्री मोड़ आदि ने

विकलांगता एक अवस्था है बीमारी नहीं

भास्कर न्यूज | चित्तौड़गढ़

विकलांगजन किसी भी प्रकार के सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से पीड़ित न हो इनके अधिकार सुनिश्चित हो। विकास योजना में विकलांगजन की भागीदारी सुनिश्चित हो।

यह विचार राकेश सेंती में आयोजित विकलांग मंच की जिलास्तरीय बैठक में उभरकर आए। केन्द्र समन्वयक आशीष त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में विकलांगजनों की भागीदारी नगण्य है, जो चिंताजनक

चित्तौड़गढ़. विकलांग मंच की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते अतिथि।

एक अध्यापक नहीं होना चिंता का विषय है। साईट सेवर्स केतन कोठारी ने कहा कि

पीड़ा के रूप में माना जाता है जो समाज ने बनाई है।

रूप की योजना बनी है, लेकिन धरातल स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। बैठक में साईट सेवर्स प्रभात सिन्हा केन्द्र समन्वयक आशीष त्रिपाठी, कार्यक्रम प्रभारी मदनगिरी गोस्वामी और संयोजित किया। बैठक में 82 विकलांगजन समेत 150 लोगों ने भाग लिया।

मुद्रक : एम. एस. प्रिण्टर्स

कट्स मानव विकास केन्द्र
सेंती (रावला), चित्तौड़गढ़ 312025, फोन : (01472) : 241472 फैक्स : 247715
E-mail: chd@cuts.org, Website: www.cuts-international.org